RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 184 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

फडणवीस ने सुलझाई बीजेपी की कलह...

24 घंटे में निलेश ने लिया यू टर्न

निलेश राणे ने रिटायरमेंट की पोस्ट भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी ...

मुंबई : लोकसभा चुनाव के पहले ही कोंकण भाजपा में शुरू हुई कलह को कम करने में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफलता मिली है। स्थानीय स्तर पर पार्टी में तवज्जो न मिलने से नाराज पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र

निलेश राणे ने अचानक राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी थी।

मंगलवार को निलेश राणे ने कहा था कि अब राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। निलेश की इस घोषणा के बाद बीजेपी नेता सकते में आ गए। बुधवार को सुबह कैबिनेट मंत्री व सिंधुदुर्ग के पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण राणे परिवार के जुहू स्थित बंगले पर पहुंचे और इसके बाद वे निलेश को लेकर सीधे देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित बंगले पर पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री के साथ चर्चा

बताया गया कि पहले निलेश राणे और रवींद्र चव्हाण के बीच तीन घंटे तक चर्चा हुई उसके बाद दोनों नेता सीधे देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित बंगले पर पहुंचे। यहां बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद निलेश राणे ने 24 घंटे के अन्दर ही राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने बीजेपी में काम करते रहने की इच्छा जताई है। फडणवीस के बंगले से बाहर निकलने के बाद रवींद्र चव्हाण और निलेश राणे एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए। रवींद्र चव्हाण ने निलेश राणे की नाराजगी का कारण बताया और सबके सामने निलेश राणे को आश्वासन दिया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी, हालांकि निलेश राणे ने बिना कुछ कहे चुप रहना ही बेहतर समझा। निलेश राणे ने रिटायरमेंट की पोस्ट भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है। निलेश राणे ने अचानक राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। मंगलवार को निलेश राणे ने कहा था कि अब राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

कार्यकर्ताओं पर नहीं होगा अन्याय

रवींद्र चव्हाण ने कहा कि कोंकण और सिंधुदुर्ग में निलेश राणे के नेतृत्व में कार्य करेगी। किसी भी छोटे कार्यकर्ता पर अन्याय नहीं होगा। चर्चा थी कि ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव में भी उनके कार्यकताओं की नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए निलेश नाराज थे। रवींद्र चव्हाण के साथ भी उनके टकराव की खबरें चल रहीं थीं। बुधवार को मंत्री चव्हाण के साथ उनकी देवेन्द्र फडणवीस से भी सकारात्मक चर्चा हुई है। उपमुख्यमंत्री ने उन्हें संगठन का काम करते रहने के लिए मना लिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्यकताओं की भावनाएं वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचे और उस अमल किया जाएगा।

पालघर में एक फार्म हाउस में ड्रग्स की
फैक्ट्री का खुलासा

सात गिरफ्तार... एक देशी कट्टे के साथ
251 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद

मुंबई: मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़े जाने का सिलसिला जारी है. पुणे, नाशिक और सोलापुर के बाद अब पालघर में भी ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. पालघर में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री एक फार्म हाउस में चल रही थी. एमबीवीवी पुलिस ने वहां से 38 करोड़ की ड्रग्स के साथ सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पिछले 15 दिनों में मुंबई पुलिस, एनसीबी, डीआरआई और मीरा भायंदर पुलिस 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स बरामद कर चुकी है.महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल एरिया के बाद अब फॉर्म हाउस में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. मीरा-भयंदर-वसई-विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पालघर जिले के मोखाडा में एक फार्म हाउस से 38 किलो ड्रग्स बरामद की है. पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच यूनिट एक को भयंदर पूर्व की बिन्यासा रेसीडेंसी लॉज में चार लोगों के छिपे होने की टिप मिली थी. पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो उनके पास से एक देशी कट्टे के साथ 251 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उसके तार पालघर के फार्म हाउस से जुड़े मिले. मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर ड्रग पकड़ी गई है. मुंबई की साकीनाका पुलिस ने नासिक से 300 करोड़ रुपये की, एनसीबी ने पुणे के जंगल में दो फैक्ट्री से तकरीब 50 करोड़ की, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोलापुर की फैक्ट्री से 100 करोड़ की, डीआरआई ने संभाजी नगर से 250 करोड़ की और अब एमबीवीवी पुलिस ने पालघर के फॉर्म हाउस से 38 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है. सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि राज्य में ड्रग्स की इतनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाने लगी हैं? जानकारों के मुताबिक एक तरफ ड्रग्स की डिमांड बढ़ी है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ी है. चूंकि एमडी ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और केमिकल आसानी से मिल जाता है इसलिए ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने लगा है. दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार की ड्रग्स के खिलाफ सख्ती भी बढ़ी है.

खाद्य और सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करनेवालों पर सख्ती

fssai
Food Safety and Standards Authority of India

मुंबई : लगभग सारे त्योहार बीत जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जागी है। आधे से अधिक त्योहार के बाद महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की तरफ से मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई शहर में एफडीए खाद्य और सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करनेवालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत एफडीए द्वारा १३ विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें मिठाई की दुकानों का निरीक्षण करेंगी और नमूनों को लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेजेंगी। वहीं होटलों के बाद अब मिठाई के दुकानों की बारी आने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर
अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मनोज जरांगे

मुंबई : कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गई 40 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। मराठा आरक्षण की मांग को राज्य में पुनः सुर्खियों में लाए 40 वर्षीय जरांगे ने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में अपना आंदोलन शुरू किया।

अनशन पर बैठने से पहले जरांगे ने संवाददाताओं से कहा, ''मराठा आरक्षण पर फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) ने मुझसे 40 दिन इंतजार करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा (फैसला) नहीं किया इसलिए मैंने अपने गांव में आमरण अनशन करने का फैसला किया है।'' जरांगे ने इस साल सितंबर में भी इस गांव में भूख हड़ताल की थी और मांग की थी कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। उन्होंने 14 सितंबर को भूख हड़ताल समाप्त करते हुए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए 24 अक्टूबर तक 40 दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा, ''मुझे बताया गया था कि राज्य भर में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए पुलिस मामले दो दिन के भीतर वापस ले लिए जाएंगे। यह आश्वासन दिए हुए 41 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी मामला वापस नहीं लिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार मराठा समुदाय को जानबूझकर गुमराह कर रही है।'' जरांगे ने कहा, ''माली समुदाय को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य कृषि माना जाता है।

एफडीए का ध्यान विदेशी दवा खरीद पर

मुंबई : राज्य में खुदरा और थोक दवा विक्रेता बड़ी मात्रा में विदेशों से दवाएं खरीदते हैं। इससे राज्य में नकली दवाओं के आने की संभावना बढ़ गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं कि नागरिकों को अच्छी और गुणवत्ता वाली दवाएं मिलें। इसके मुताबिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी विभागीय संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षकों को खुदरा और थोक विक्रेताओं से खरीदी जाने वाली दवाओं पर निगरानी रखने का आदेश दिया है।

संपादकीय / लेख

आपस में लड़ता विपक्ष

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तेज होती तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो कड़वा विवाद सामने आ गया, उसके नतीजे न तो मध्य प्रदेश तक सीमित रहने वाले हैं और न ही विधानसभा चुनावों तक। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कह भी दिया है कि जब लोकसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे की बात होगी, तब यूपी में कांग्रेस के साथ वह वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उनके साथ मध्य प्रदेश में किया गया है। हालांकि यह बात पहले से कही जाती रही है कि विपक्षी दलों का कठ.ऊकअ. गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर और लोकसभा चुनावों के लिए किया गया है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी को समझ न आए। लेकिन सवाल यह है कि अगर बात इतनी ही साफ थी तो फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनावों को लेकर उससे कोई बातचीत शुरू ही क्यों की। क्यों उन नेताओं को इन चुनावों की रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया और जैसा कि समाजवादी पार्टी का दावा है, उसके लिए छह सीटें छोड़ने की तैयारी भी दिखाई गई और क्यों बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए? इस प्रकरण पर कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के बयान पर दी है उससे इतना जरूर स्पष्ट होता है पार्टी इस मसले पर बचाव की मुद्रा में नहीं है।

उसका कहना है कि मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की मदद करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बहरहाल, इस आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी के बीच भी कोई कठ.ऊकअ. गठबंधन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। समाजवादी पार्टी ने भी यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के साथ लोकसभा चुनावों में गठबंधन नहीं करेगी। उसका कहना सिर्फ यह है कि उस समय कांग्रेस के साथ जैसे को तैसा की तर्ज पर व्यवहार किया जाएगा। इसका सही मतलब दरअसल क्या है यह उसी समय स्पष्ट होगा, लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर सचमुच विपक्षी दल कठ.ऊकअ. गठबंधन को लेकर गंभीर हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने मतभेदों को निपटाने का कोई बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। जो मतभेद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उपजे हैं, वे अअढ समेत तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ भी उभर सकते हैं। ऐसे में एक-दूसरे की सार्वजनिक आलोचना करते ये दल जब कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव के मौके पर गलबंहिया डाले नजर आएंगे तो आम मतदाताओं के लिए उनके गठबंधन की विश्वसनीयता स्वाभाविक ही संदिग्ध होगी।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

वीजा अवधि उल्लंघन, विदेशी नागरिकों के लिए जल्द बनेगा डिटेंशन सेंटर

अदालत से बरी होने के बाद, विदेशी नागरिकों का ठिकाना पुलिस स्टेशन

मुंबई: मुंबई के परेल स्थित भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के बगल में जल्द ही डिटेंशन सेंटर का निर्माण किए जाने के संकेत मिले हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव अंतिम चरण में है। क्योंकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने डिटेंशन सेंटर इमारत के पुनर्गठन के लिए गृह विभाग को 5 करोड़ रुपये से अधिक का कोटेशन भेजा है। बता दें कि, लगभग एक दशक पहले दो पाकिस्तानी नागरिकों को छह महीने तक मुंबई एक पुलिस स्टेशन में रखना पड़ा था, दोनों को एक मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में दोनों को अदालत ने बरी कर दिया था, चूंकि उनका वीजा समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें तब तक पुलिस स्टेशन में रखना पड़ा।

कैदी विनिमय कार्यक्रम के तहत उन्हें उनके देश वापस नहीं भेजा जा सका था। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने और विदेशी नागरिकों को पुलिस स्टेशन में रखने की बजाए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए, डिटेंशन सेंटर इमारत निर्माण करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, इस डिटेंशन सेंटर इमारत में करीब 150 विदेशी नागरिकों को रखा जा सकता है। इनके लिए कैरम, टेलीविजन, शतरंज, वॉलीबॉल, जिम, स्कूल और पुस्तकालय जैसी मनोरंजक गतिविधियां स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इन्होने बताया कि, हालांकि एक ढांचा तैयार है जो ग्राउंड प्लस यानी दो मंजिला है, लेकिन हमें गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित विदेशी अधिनियम के आदेश के अनुसार पूरे परिसर का नवीनीकरण करना होगा।

इस इमारत में 30 कमरे हैं, जिनमें से 18 पर महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस),10 पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी),2 पर राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) का कब्जा है। एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, संबंधित अधिकारियों को इमारत खाली करने के लिए कहा जाएगा और उन्हें वैकल्पिक कार्यालय प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी नवीनीकरण का काम शुरू करेगा। वर्तमान में मुंबई या राज्य में कहीं भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जहां ऐसे लोगों को रखा जा सके, इसके लिए एक डिटेंशन सेंटर आवश्यक है। क्योंकि कई मामलों में जो लोग वीजा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं वे आपराधिक नहीं हैं और उन्हें जेल में बंद नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान में कहां रहते है विदेशी नागरिक

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में ऐसे निर्वासन मामले में उस विदेशी नागरिक को कहां रखना है, यह उस व्यक्ति की पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ मामलों में पुलिस नोटिस देकर उन्हें हर दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहती है या फिर उन्हें निर्वासन की औपचारिकता पूरी होने और वापस भेजे जाने तक पुलिस स्टेशन में ही रखती हैं। यदि व्यक्ति बेहद कुख्यात है और उसे जारी किए गए दिशानिर्देशों का वो पालन नहीं करता है, तो हम उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हैं।

एमएसएफ के हाथों में डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा

डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा, महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, डिटेंशन सेंटर की निगरानी पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा क्क) द्वारा की जाएगी। क्योंकि यह विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों से संबंधित मुद्दों से भी निपटता है। डीसीपी का कार्यालय संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों के संपर्क में रहेगा, सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बंदियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाए।

किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही, वित्तीय संकट में फंसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं

मुंबई: गुजरात तक जानेवाली बुलेट ट्रेन के लिए एक ही दिन में ६ हजार ६०० करोड़ रुपए की निधि मंजूर की जाती है। बुलेट ट्रेन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बारिश न होने से सूखे के संकट की मार झेल रहे किसानों के बारे में यह घाती सरकार बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। साथ ही किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर पापियों के राज में प्रकृति भी कुपित हो रही है। इसके प्रहार से वित्तीय संकट में फंसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए आने वाले समय में हमें फसल बीमा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह का जोरदार हमला घाती सरकार पर करते हुए विधान परिषद में विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे ने कहा कि 'सरकार आपके द्वार' लेकिन सरकार भेज रही है 'मौत के द्वार', ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है।

शिवतीर्थ पर आयोजित शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधान परिषद में विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे ने कहा कि दशहरा सम्मेलन सिर्फ शिवाजी पार्क पर होता है। गद्दारों का दशहरा सम्मेलन नहीं होता है। फिलहाल, मौजूदा समय में गद्दार दिल्ली जाकर मुजरा करते हैं। ये महाराष्ट्र के विचारों के गद्दार हैं। इन सभी के कारण गद्दार अब घर बैठने वाले हैं। इनके लिए चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

मुंबई में शुरू सरकारी परियोजनाओं के चलते अधिक प्रदूषण?

मुंबई: मनपा ने राज्य के सभी निर्माण संबंधित प्राधिकरणों पर कम तो निजी बिल्डरों पर प्रदूषण रोकने के लिए अधिक दबाव बनाया है। बिल्डरों ने मनपा की ओर से बढ़ रहे दबाव को लेकर नाराजगी जताई है। महारेरा ने बिल्डरों के समर्थन में उतरकर मनपा को करारा जवाब दिया है। महारेरा ने स्पष्ट कहा है कि मुंबई में शुरू सरकारी परियोजनाओं के चलते अधिक प्रदूषण हो रहा है। निजी बिल्डरों ने हमेशा मनपा की नियमावली का पालन किया है। यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। सरकारी परियोजनाओं पर भी प्रदूषण मामले में अंकुश होना जरूरी है, जबकि मनपा अपने सिर का बोझा निजी बिल्डरों पर धकेलकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है।

मनपा सूत्रों के अनुसार, दो दिन पहले निर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न प्राधिकरणों के सदस्यों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मनपा आयुक्त आईएस चहल ने निजी बिल्डरों के परियोजनाओं में हो रही लापरवाही से प्रदूषण बढ़ने की बात कही, जिस पर रेरा के सदस्य ने कड़ी नाराजगी जताई। इस बीच दोनों के बीच तनातनी देखने को मिली। महारेरा के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने मीडिया को बताया कि प्रदूषण बढ़ाने में सरकारी परियोजनाओं का हिस्सा अधिक है। निजी परियोजनाओं से कम बल्कि सरकारी परियोजनाओं से वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है।

बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की छवि प्रदूषण के चलते अब खराब होने लगी है। प्रदूषण मामले में मुंबई ने दिल्ली को भी कई गुना पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में मनपा की चिंताएं बढ़ गई हैं।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 26 अक्टूबर 2023

मनपा के विभाग अधिकारी की कार्रवाई से पकड़ा गया लाखो का माल

मुंबईः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने सोमवार (२३ अक्टूबर) को वसई पूर्व में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर कार्रवाई की गई है । मनपा द्वारा यह कार्रवाई अबतक की सबसे बड़ी बताई जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों एवं अधिसूचनाओं तथा राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक २६ अप्रैल २०२२ के अनुसार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग,बर्तन और थर्माकॉल गैर-अपघटनीय वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक वसई-विरार शहर महापालिका में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स के माध्यम से मनपा क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए पालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ने इसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

२३ अक्टूबर को सुबह ७ बजे वसई विरार शहर मनपा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के सहायक आयुक्त सुकदेव दरवेशी द्वारा प्रभाग 'डी' में मुनबिन को औ.हाऊसिंग सोसायटी गाळा क्रं.८,समर्थ रामदास नगर,नवघर पूर्व व तिरूपति ट्रेड सेंटर के सामने,नवघर,वसई पूर्व स्थित सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान टाटा आयशर और महिंद्रा बोलेरो वाहनों में ३९७५ किलोग्राम और टाटा एस वाहन में ७०२ किलोग्राम कुल ४६७७ किलोग्राम (४.५ टन इससे अधिक) एकल-उपयोग प्लास्टिक इतनी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। इस प्लास्टिक की कीमत ७०१५५० रुपये तक होने का अंदाजा लगाया गया है।

पुणे से नागपुर तक युवा संघर्ष यात्रा

मुंबईः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और विधायक रोहित पवार ने आज पुणे से नागपुर तक युवा संघर्ष यात्रा की शुरूआत की। यह यात्रा ८०० किमी की दूरी तय करेगी। यह कोई छोटी नहीं है, ४२ से ४५ दिन की यात्रा है। युवा संघर्ष यात्रा नई पीढ़ी की एक पहल है। यह युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ानेवाली यात्रा है। इतना ही नहीं, गांवों के युवाओं को प्रोत्साहित और मार्गदर्शक करने के लिए उक्त यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे के तिलक मेमोरियल में युवा संघर्ष यात्रा की आशीर्वाद सभा में बोलते हुए व्यक्त किया। शरद पवार ने कहा कि युवा राज्य में बदलाव देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इस युवा संघर्ष यात्रा के माध्यम से वह प्रक्रिया पूरी होगी, जिसकी यह शानदार शुरूआत है। युवाओं का मुद्दा उठाया गया और सरकार को संविदा भर्ती का पैष्ठसला वापस लेना पड़ा। जब संघर्ष यात्रा नागपुर पहुंचेगी, तो मुझे यकीन है

कि सत्ता को बरकरार रखनेवाले सत्ताधारी लोग लोकतंत्र और शांति की राह पर चल रहे युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी ने इसकी अनदेखी की तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। युवा संघर्ष यात्रा नई पीढ़ी का सवेरा है। यह नई पीढ़ी को आत्मविश्वास और प्रोत्साहन देगी, ऐसा शरद पवार ने कहा। रोहित पवार की संघर्ष यात्रा कल पुणे से शुरू हो गई है और इस यात्रा में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। शरद पवार और रोहित पवार पर जेसीबी से युवाओं ने पुष्पवर्षा कर जोरदार स्वागत किया। पुणे में तिलक स्मारक के पास यह यात्रा पहुंची और तिलक स्मारक हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि युवा संघर्ष यात्रा युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। यह कार्यक्रम समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है। शरद पवार ने कहा कि इस यात्रा से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। शरद पवार ने आगे कहा कि हम युवाओं की मांगों को पूरा करने के लिए मध्यस्थता करेंगे। युवाओं की सभी मांगों को इकट्ठा कर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि हम एक बैठक बुलाएंगे, उस समय हम इन मांगों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री से सकारात्मक जवाब प्राप्त करेंगे।

मुस्लिम आरक्षण को तत्काल बहाल किया जाए: नसीम खान

मुंबई : प्रदेश कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री मो. आरिफ (नसीम) खान ने कहा कि जब 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी, तब मुस्लिम समाज की 50 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इस पर अमल भी शुरू हो गया था। साथ ही बंबई उच्च न्यायालय ने भी इस आरक्षण को जारी रखने पर मुहर लगा दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद आरक्षण पर रोक लगा दी। बार-बार मांग के बावजूद मुस्लिम समुदाय को आरक्षण नहीं दिया। खान ने यह बात राज्य के विभिन्न जिलों से आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में कही। इस बैठक में बांबे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय थिप्से, पूर्व पूर्व सांसद डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, राकांपा के नसीम सिद्दीकी , पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहानी, निजामुद्दीन राइन और राज्य के विभिन्न जिलों से

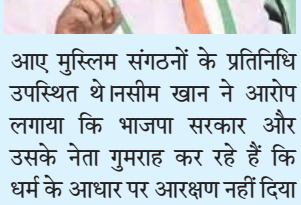

आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।नसीम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके नेता गुमराह कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस प्रदेश में हर कोई जानता है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, धर्म के नाम पर नहीं। आरक्षण के संबंध में लिया गया निर्णय पिछड़ेपन पर आधारित था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा और समानता के आधार पर और संविधान के ढांचे के भीतर आरक्षण जारी रखने के निर्णय को मंजूरी दे दी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को उसके पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

नसीम खान ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की तरह जिस तरह बिहार में जातिवार जनगणना की गई है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जातिवार जनगणना शुरू की जाए। इस संबंध में उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राज्य में जातिवार जनगणना शुरू करने की मांग का स्वागत किया। खान ने कहा कि यदि राज्य में जातिवार जनगणना शुरू की जाती है तो राज्य में जाति, जनजाति के लोगों की संख्या राज्य और देश के सामने आ जाएगी, जिससे सभी समुदाय के घटकों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।

स्कूलों का किराया वृद्धि 5 वर्षों के लिए निलंबित

मुंबई : मुंबई महापालिका भवनों में स्कूलों के क्लास रूम के लिए वार्षिक किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। एक महीने के लिए प्रति कक्षा 500 रुपये किराया लिया गया। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि, राज्य के कुपोषण एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार की मराठी भाषा संरक्षण नीति के अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और मराठी मीडियम` के जूनियर कॉलेज से नाममात्र शुल्क लिया जाना चाहिए। ये मांग दीपक सावंत ने बयान देकर की है। महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल से मुलाकात के बाद उन्होंने डे स्कूलों के सालाना किराये में 10 फीसदी बढ़ोतरी की नीति को अगले 5 साल के लिए निलंबित करने की मांग की। इस वर्ष की कक्षा किराया दर अगले 5 वर्षों तक समान रहेगी, ऐसा मनपा आयुक्त ने इस समय निर्देश दिया है।

विरार पुलिस स्टेशन को मिली सफलता!

कार्यवाही में पकड़े गए दो मोटरसाइकिल चोर

वसई : दुपहिया वाहन चोरी करने के मामले में विरार पुलिस स्टेशन की अपराध जांच शाखा की टीम ने २ शातिर चोर को गिरफ्तार कर ४ अपराधों का खुलासा किया है। यह कार्रवाई डीसीपी (परिमंडल ३) सुहास बावचे व एसीपी रामचंद्र देशमुख के मार्गदर्शन में विरार थाने के सीनियर पी.आई.राजेन्द्र कांबले व पी.आई. (अपराध) अभिजित मडके के नेतृत्व में अपराध जांच शाखा के स.पो.नि.ज्ञानेश फडतरे की टीम ने की है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने सोमवार को दी है। पुलिस ने बताया कि,शिकायतकर्ता पवनकुमार जटाशंकर शर्मा (२५),ने १६ अक्टूबर २०२३ को डोंगरपाडा,विरार (प.), स्थित मोटरसाइकिल क्र. एम. एच. ४८-सी.एच. ८२८९ ने खड़ी किया था।लेकिन,अज्ञात चोर उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गए,शिकायतकर्ता ने संबंधित शिकायत विरार थाने में दर्ज कराया

था।मामले मे पुलिस ने अज्ञात चोर के ऊपर कलम ३७९ के तहत केस दर्ज कर आगे की तहकीकात में जुट गई थी।पुलिस ने बताया कि उपरोक्त अपराध के अनुसरण में, विरार अपराध जांच शाखा के अधिकारी व कर्मचारी ने अपराध स्थल पर सीसीटीवी और गुप्त मुखबिर के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी अनिकेत जोशी (२३) व तैवान कुरेशी (२४) को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बताया कि,जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई,उनके पास से उक्त अपराध के साथ-साथ विरार पुलिस स्टेशन के अन्य ३ अपराधों में ३ कुल ४ मोटर साइकिलें जब्त की गई हैं।

२५ लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में

मुंबई, देश की दरकती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच एक खबर हैरान करनेवाली है। पिछले ९ वर्षों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने करीब २५ लाख करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते में डालने का अर्थ है कि ऐसी राशि जिसे बैंक अपने कर्जदार से वसूल पाने में नाकाम रहे हैं। बट्टे खाते की ये खबर आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में दी है। सूरत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय एझावा ने

ये जानकारी आरटीआई से हासिल की है। मगर हैरानी की बात है कि इक्का-दुक्का मीडिया को छोड़कर किसी भी मीडिया हाउस ने इस खबर को जगह नहीं दी। इस बारे में १७-१८ अक्टूबर को मीडिया समूह 'द फ्री प्रेस जर्नल' ने बताया कि एनडीए सरकार के ९ साल के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से १०.४१ लाख करोड़ रुपए एवं शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से १४.५३ लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी गई। इन दोनों का योग २४.९५ लाख करोड़ रुपए होता है। इस जानकारी से बड़े पैमाने पर वित्तीय फेरबदल का खुलासा हुआ है। यह जानकारी बेहद हैरान करने वाली है और इसको लेकर बहस और चचाओं का दौर शुरू हो गया है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा कि आरबीआई के खुलासे में सिर्फ सांख्यिकीय जानकारी को ही शामिल किया गया है, जबकि इसके डिफॉल्टरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। इसके बावजूद इसे हिंदुस्थान के वित्तीय इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कर्ज माफी धनराशि बताया जा रहा है।

बट्टे खाते में डाले गए २५ लाख करोड़ रुपए का बोझ बड़े पैमाने पर आम नागरिकों और किसानों पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत की तुलना में उनके द्वारा कम ऋण लिया जाता है। अधिकांश मध्य वर्ग और ग्रामीण आबादी तो बैंकों से कर्ज ही नहीं लेती, बल्कि अपनी बचत की अधिकांश जमापूंजी बैंकों में ही निवेश करती है। इस राइट-ऑफ के प्रमुख लाभार्थी वे पूंजीपति और कॉर्पोरेट घराने हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में बैंकों से उधार लेकर पैसों का गबन किया और ऑफ-शोर खातों में रकम डालकर बाद में देश छोड़ गए। आरबीआई ने ऋणदाताओं के आंकड़ों को इकट्ठा करने, संग्रहित करने और प्रसारित करने के लिए 'सीआरआईएलसी' बनाई है। जून २०२३ तक सीआरआईएलसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ५ करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वाले ३,९७३ खातों को बट्टे खाते में डाल दिया है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 26 अक्टूबर 2023

मुंबई में मिली 100 करोड़ की MDMA, बोरियों में भरकर फेंकी थी

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई पुलिस और देवला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सोमवार की आधी रात को करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद की। बताया जाता है कि गिरना नदी के तल से ड्रग्स की बरामदगी की गई। ड्रग्स माफिया ललित पाटिल की 300 करोड़ की ड्रग्स फॅक्टरी के पकड़े जाने के बाद लगातार इसमे खुलासा हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद ड्रग की कीमत लगभग 100 करोड़ आंकी गई है हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने आंकड़े नही जारी किए है लेकिन मिली ड्रग्स की कीमत सैकड़ो करोड़ के होने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने नासिक के शिंदे गांव में ललित पाटिल की एमडी ड्रग्स फैकट्री को नष्ट करने के साथ ही करीब 300 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई थी। वहीं कुछ ही दिन पहले मामले में फरार चल रहे ललित पाटिल को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार किए गए ललित पाटिल के ड्राइवर सचिन वाघ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने ड्रग्स को देवला की गिरना नदीं में फेंक दिया था।

ड्रग्स की बोरियां बरामद की

इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम ने आधी रात की सर्च ऑपरेशन चलाया और रात करीब 2 बजे नदी से ड्रग्स की बोरियां बरामद कीं. इसके बाद ड्रग्स की बोरियों को तलाशने का काम मंगलवार की सुबह भी जारी था।

ड्रग्स को नष्ट करने के मकसद से नदी में फेंका

गिरफ्तार ललित पाटिल के ड्राइवर सचिन वाघ ने पुलिस को बताया कि उसने ड्रग्स को खत्म करने के इरादे से दो बोरी ड्रग्स नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपये बताई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में ड्रग्स की मामला चर्चा में बना हुआ है, इस मामले में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपी भूषण पाटिल को जांच के लिए नासिक लाया गया था। वहीं बाद में ड्रग माफिया ललित पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे भी दो दिन पहले देर रात मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए नासिक लाई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ललित पाटिल ने ड्रग मनी से 8 किलो सोना खरीदा था। इसलिए पुलिस अब उन सभी सुनारों की जांच करने जा रही है, जिनसे उसने सोना खरीदा था।

उद्धव पर शिंदे के वार से बिफरे राउत

वे खुद हमास, कांग्रेस की चुनौती- अभी करा लें चुनाव...

महाराष्ट्र : दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने रैली की। जहां उद्धव ठाकरे ने विजयदशमी के मौके पर शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया तो आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने रैली की। रैलियों में दोनों ही नेताओं ने एक-दूसरे पर जमकर प्रहार किया है। एकनाथ शिंदे ने रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब ठाकरे को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे की वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है।

वडेट्टीवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को जो समर्थन मिल रहा, उसे देखते हुए एकनाथ शिंदे ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'उन्हें चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए, जिसके बाद पता चल जाएगा कि कौन असली है और नकली। इसी से पता चलेगा कि किसे जनता का समर्थन मिल रहा है और कौन शिवसेना के विचारधारा का पालन करती है।'

पिज्जा लाने में देरी से बिफरा शख्स... डिलिवरी ब्वॉय को पीटा, हवा में चलाईं गोलियां

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पुणे में पिज्जा लाने में हुई देरी से नाराज एक व्यक्ति ने पिज्जा डिलिवरी ब्वॉय को कथित रूप से पीटा और हवा में गोलियां चलाईं। पुलिस ने 27 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की पहचान चेतन पडवाल के रूप में हुई है। घटना सोमवार रात की है। लोनीकंद पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शहर के वाघोली इलाके की पिज्जा की दुकान से पिज्जा ऑर्डर किया था। ऋषिकेश अन्नपूर्वे जब पडवाल के घर पहुंचा, तो उसने पिज्जा लाने में देरी होने पर उसे कथित रूप से अपशब्द कहे और मारपीट की। अन्नपूर्वे के दो साथी जब यह जानने आए कि पडवाल ने उनके साथी को क्यों पीटा? तो उसने उनसे भी मारपीट की। अधिकारी ने बताया कि पडवाल गुस्से में अपने मकान के पास खड़ी अपने वाहन की ओर भागा, उसने पिस्तौल निकाली और हवा में गोलियां चला दीं। पिज्जा दुकान के कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने पडवाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत गिरफ्तार कर लिया।

भिवंडी में पूजा करने जा रहे पति पत्नी से लूट की वारदात... मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी के कामतघर इलाके स्थित एक पति पत्नी के साथ लूट की वारदात तब हुई जब वे अपने घर से दो पहिया वाहन पर सवार पूजा करने के इरादे जा रहे थे। इस मामले में नारपोली पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कामतघर इलाके स्थित ब्रम्हानंद नगर के रहने वाले प्रमोद पांडुरंग जाधव 51 वर्ष रात साढ़े दस बजे अपनी पत्नी के साथ दो पहिया वाहन से पूजा करने के उद्देश से घर से निकले थे। और जैसे ही वे बालाजी किराना दुकान के पास पहुंचे तभी उनके इलाके में रहने वाला अभिमन्यु उर्फ मन्या झा ने उनकी पत्नी के गले से 80 हजार रुपए कीमत का सोने का लक्ष्मी हार व मंगलसूत्र छीन लिया। जब उन्होंने इसका विरोध करना चाहा तो आरोपी ने चाकू निकाल कर उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आया तो उसे खल्लास कर दूंगा। इस तरह आरोपी दहशत निर्माण कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने महिला के पति प्रमोद पांडुरंग जाधव की शिकायत पर आरोपी अभिमन्यु उर्फ मन्या झा के खिलाफ गुनाह रजिस्टर नंबर 864/2023 में भादवी कलम 394 व महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की कलम 37 (1), 135 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक व्ही. बी. बढे कर रहे है।

'शिंदे सरकार नीतिगत पक्षाघात से पीड़ित'

मराठा आरक्षण को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के तीखे बोल...

महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र पर बुधवार को जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार नीतिगत पक्षाघात से पीड़ित है। सुप्रिया सुले की यह टिप्पणी मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा आरक्षण की मांग के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद आई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जरांगे ने सितंबर माह के बीच अपना पहला अनशन खत्म करते समय सरकार को ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। शिंदे सरकार ने तब आश्वासन दिया था कि मराठा आरक्षण 40 दिनों में होगा, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीखा हमला करते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार को नीतिगत पुंग करार दिया। बता दें मराठा आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकार को दी गई 40 दिन की समय सीमा खत्म हुई। आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बुधवार सुबह जालना जिले की अंबाद तहसील के अंतर्गत अंतरवाली सरती गांव में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। मनोज जरांगे (40) ने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर अगस्त के अंत में अंतरवाली सारती गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। जरांगे ने 14 सितंबर को विरोध वापस ले लिया और समुदाय को कोटा देने के लिए सरकार के लिए 40 दिन की समय सीमा तय की (जो 24 अक्तूबर को खत्म हुई)।

ड्रग्स मामले में शिंदे गुट ने अब निकला एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का कनेक्शन

मुंबई : ड्रग्स मामले में गिरफ्तार ललित पाटिल को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) गुट एवं शिवसेना (उबाठा) काफी अधिक आक्रामक है। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं। अब शिवसेना शिंदे गुट ने पलटवार किया है।

शिवसेना प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने राकां सांसद सुप्रिया सुले और राकां के राष्ट्रीय महासचिव विधायक जितेंद्र आव्हाड के साथ ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सलमान फालके का फोटो जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की है। कायंदे ने कहा है कि ड्रग्स माफियाओं को कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने कहा है कि नासिक ड्रग्स मामले में ललित पाटिल को गिरफ्तार किया गया था। तब यह सामने आया था कि 2020 में उद्धव ठाकरे ने ललित पाटिल के हाथ में शिवबंधन बांधा था। पाटिल के हाथ में शिवबंधन बांधते हुए उद्धव का फोटो भी वायरल हुआ था। जांच में सात झआठ नाम सामने आये थे। जिसमें सलमान फालके का नाम था उसके पास से 54 ग्राम एमडी बरामद हुआ था।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 -4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com